



हरित क्रांति को नई ताकत देने के लिए भारत-अमेरिकी पहल

विनोद वाष्पाय

नई दिल्ली। थक रही हरित क्रांति को नई ताकत देने के लिए 'भारत-अमेरिकी ज्ञान पहल' का काम शुरू हो गया है। इसका फैसला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जुलाई में अमेरिका यात्रा में लिया गया था। अब राष्ट्रपति जार्ज बुश की फरवरी में संभावित भारत यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में जहां विदेश सचिव श्याम शरण और अमेरिकी अवर सचिव निकोलस बर्न के बीच वार्ता हुई है, वहीं पिछले सप्ताह 'एग्रोकल्चर नॉलिज इनीशिएटिव' के लिए बने भारत-अमेरिकी बोर्ड की भी पहली बैठक हुई।

संप्रग सरकार कृषि की उपेक्षा पर चिंता व्यक्त करती रही है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दस प्रतिशत की विकास दर हासिल करने के लिए कृषि की विकास दर डेढ़ से बढ़ाकर चार प्रतिशत करना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बाधा ज्ञान (नई टेक्नोलॉजी) की ही है। यही वजह है कि मनमोहन सरकार ग्रामीण आमदनी में इजाफा करने के लिए इस इनीशिएटिव पर खास जोर देना चाहती है।

कृषि संबंधी 'भारत-अमेरिकी ज्ञान पहल' की पहली बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय कृषि

अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डा. मंगला राय ने किया। उद्योग प्रतिनिधियों के तौर पर बैंकेश्वर और आई.टी.सी. ग्रुप के प्रतिनिधि भी इसमें आमंत्रित थे, लेकिन वे भाग नहीं ले पाए। तीन सदस्य एकेडेमिया के थे।

उनमें से एक गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डा. पी.एल. गीतम ने बताया कि सरकार पिछले पन्द्रह साल से लगातार गिर रही कृषि उत्पादकता से परेशान है। इससे कृषि उत्पादों को सस्ता रखना मुश्किल हो रहा है, साथ ही किसानों की आमदनी भी सुरक्षित नहीं रह पा रही। कृषि उत्पादकता बढ़ाये बिना भारत विश्व बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकता और न ही देशी बाजार को बचाये रख सकता।

हाल में चीनी राजमा ने जिस तरह भारतीय राजमा को पछाड़ा है, वह एक उदाहरण है। सूत्रों के बताया कि बोर्ड की पहली बैठक में 'भारत-अमेरिकी नॉलिज इनीशिएटिव' के लिए चार क्षेत्रों का चयन किया गया। ये हैं : हाई टेक कृषि के लिए प्रोफेशनल तैयार करना, कृषि शिक्षा के नये कोर्स तैयार करना, खाद्य प्रसंस्करण को गति प्रदान करना, प्रसंस्करण के दौरान पैदा होने वाले उप-उत्पादों को इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी विकसित करना।